

सार-समाचार

कठुआ रेप केस में आया नया मोड़, बच्ची से रेप तो हुआ पर गैंगरेप संभव नहीं

जम्मू। कठुआ रेप केस हर दिन उलझता ही जा रहा है। हर दिन इस मामले में नये-नये मोड़ आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है पर उस पर भी सन्देह बना हुआ है वहीं मीडिया में उजागर हुई बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को नया मोड़ दिया है। स्वास्थ्य विभाग के एक डाक्टर ने अपना नाम न छापने की बात पर कहा कि मीडिया में यह कहा जा रहा है कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है, यह बात सही नहीं है बल्कि बच्ची के साथ रेप तो हुआ पर गैंगरेप नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बच्ची के साथ रेप होना तो संभव है पर जिस तरह से बार-बार गैंगरेप की बात कहकर मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे चोट के निशान बच्ची के शरीर पर नहीं मिले हैं।

सूत्रों की मानें तो चार्जशीट को लेकर विरोधाभास पहले दिन से ही हो रहा है। आरोपियों ने भी कोर्ट में अपनी पहली पेशी पर नाकों टेस्ट की मांग की थी और कहा कि था कि उससे सच सामने आ जाएगा। अब बात यहीं भी आकर सन्देह पैदा कर रही है कि क्राइम ब्रांच ने जब चार्जशीट दाखिल की थी तो उसके साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कॉपी संलग्न नहीं की थी। वहीं मीडिया में आई कुछ रिपोर्टों के बाद यह कहा गया कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है पर यह बात भी कही गई है कि बच्ची का कौमार्य भंग हुआ है और तर्क दिया गया है कि घुड़सवारी और खेलकूद से भी यह हो सकता है।

दिल्ली फोरेंसिक लेबारेट्री का खुलासा

दिल्ली की फोरेंसिक लेबारेट्री ने इस बात की पुष्टि की है कि बच्ची का वजिनल स्वेब आरोपी से मैच करता है। यह इस मामले में सबसे बड़ा सबूत है। दिल्ली की लेबारेट्री में सबूतों के 14 पैकेटों की जांच की गई है। यह सबूत दिल्ली। मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच भेजे गए हैं। इनमें वजेनिल स्वेब (यौनि की बाहरी परत), खून के सैंपल, बच्ची की आंत, साधी मिट्टी, खून से सनी मिट्टी, बच्ची की फ्राक और सलवार शामिल है। एफएसएल ने सैंपल की जांच करने के बाद रेप की पुष्टि की थी। यह भी कहा गया कि आरोपियों के डीएनए भी मैच हुए हैं।

नोटबंदी के बाद बैंकों में बढ़े जाली नोट और संदिग्ध लेनदेन के मामले

नई दिल्ली, प्रे्ट्। नोटबंदी के बाद देश के बैंकों में नकली भारतीय मुद्राओं की आमद ने पिछले सभी वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। संदिग्ध लेनदेन के बारे में अपनी तरह की पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर, 2016 में नोटबंदी के बाद बैंकों में ऐसे लेनदेन की संख्या में 480 फीसद का उछाल दर्ज किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी, सार्वजनिक व सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) में 400 फीसद से ज्यादा इजाफा दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कुल एसटीआर रिपोर्टिंग की तादाद 4.73 लाख को पार कर गई।

इंटेल मंत्रालय के अधीन आने वाली फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट (एफआइयू) के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 के मुकाबले वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थाओं में जाली नोट जमा करने की घटनाओं में 3.22 लाख बढ़ोतरी दर्ज की गई। गौरतलब है कि एफआइयू का काम मनी लाँड्रिंग और आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद देने संबंधी संदिग्ध लेनदेन का विश्लेषण करना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सीसीआर की 7.33 लाख से ज्यादा घटनाएं सामने आईं, जबकि उससे ठीक पिछले वित्त वर्ष में 4.10 लाख से ज्यादा बार बैंकों में जाली नोट पकड़ी गई थी।

गौरतलब है कि सीसीआर की पहली बार गणना वित्त वर्ष 2008-09 में की गई थी। उसके बाद नोटबंदी वाले वित्त वर्ष में इस तरह की घटना चरम पर रही। सीसीआर तभी जारी किया जाता है, जब बैंक में नकली भारतीय मुद्रा नोट (एफआइसीएन) पकड़ में आती है। एफआइयू के एंटी मनी-लाँड्रिंग नियमों के तहत जब भी बैंकों के लेनदेन में नकली या फर्जी भारतीय मुद्रा असली के तौर पर किया जाता है या कोई फर्जी या नकली नोट पकड़ में आता है, तो एफआइयू को इसकी सूचना दी जानी जरूरी होती है।

दूसरी तरफ, एसटीआर की गणना तब होती है जब बैंकों में हुए किसी लेनदेन पर संदेह उपजाता है या उस लेनदेन की व्यवहार्यता समझ में नहीं आती।

पश्चिमी तटीय इलाकों और ओडिशा में तेज हवाओं के साथ समुद्री तरंगों को लेकर चेतावनी

आईएमडी के अनुसार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों में तेज हवाओं की गति 40-50 किमी प्रति घंटे की रफतार तक पहुंचने की संभावना है।

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पश्चिमी तट के दक्षिणी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ समुद्र में भी हलचल की चेतावनी दी है। एहतियातन तौर पर मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र की तरफ नहीं जायें। आईएमडी के अनुसार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों में तेज हवाओं की गति 40-50 किमी प्रति घंटे की रफतार तक पहुंचने की संभावना है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इनफॉर्मेशन सर्विसेज (आईएनसीओआईएस) ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि आज सुबह भारत के पश्चिमी तट और लक्षद्वीप में तेज गति वाले समुद्री तरंगों का अनुभव किया जाएगा।

वहीं मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विश्वोभ के कारण उत्तर भारतीय रज्यों में वर्षा हो सकती है। अगले दो दिनों में जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और



उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विभाग ने गुरुवार को बताया कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी चल सकती है।

भारत मौसम विभाग ने कहा है, %पूर्वी भारत को छोड़ देश के अधिकांश हिस्से में अधिकतम

दुकराई दिव्यांग सकीना को लक्ष्मण ने दिया सहारा, बने जीवनसाथी

श्शोपुर । यह कहानी एक दिव्यांग महिला और उसके पड़ोस में किराना दुकान चलाने वाले युवक की है। एक पांव खराब होने पर महिला को उसके पति ने शादी के कुछ साल बाद ही घर से निकाल दिया। ससुराल ने दुकराया तो मायके आ गई, लेकिन मां-बाप की मौत के बाद भाइयों ने भी घर में रखने से इनकार कर दिया।

करीब पांच साल से अकेली रह रही

दिव्यांग महिला की पहचान पड़ोस में किराना दुकान चलाने वाले युवक से हुई। महिला मुस्लिम है और युवक हिंदू। 18 अप्रैल को इस जोड़े ने 'मुख्यमं'त्री कन्यादान विवाह सम्मेलन में सात फेरे लिए।

बोहरा बाजार निवासी सकीना का विवाह 7 वर्ष पहले हुआ था। कुछ समय बाद ही उसका तलाक हो गया। इसके बाद वह भाई के घर रहने लगी, लेकिन मां ने भी एक दिन घर से निकल जाने को कह दिया।

पांच साल से सकीना किराए का कमरा लेकर रह रही है। उसके पड़ोस में ही लक्ष्मण नाम का युवक किराना दुकान चलाता है।

दोनों में डेढ़ साल पहले पहचान हुई और फिर प्यार हुआ। लक्ष्मण के परिवार ने भी दोनों का साथ दिया और खुशी-खुशी शादी में शामिल हुए।

दुकानदार-शाहक में ऐसे पक्का हुआ रिश्ता

लक्ष्मण ने बताया कि सकीना उसकी दुकान पर सामान लेने आती थी। जब लगा कि सकीना भी उसे पसंद करती है तो उसने बातचीत शुरू की। करीब चार महीने पहले लक्ष्मण ने सकीना के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे सकीना ने स्वीकार किया।

प्रोत्साहन राशि नहीं नौकरी चाहिए
अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 2

लाख रुपये एवं दिव्यांग महिला से विवाह करने वाले सामान्य पुरुष को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 50 हजार रुपये दिए जाते हैं। हालांकि लक्ष्मण का कहना है कि उसे कोई प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए।

सकीना को चपरसी या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नौकरी मिल जाए तो वह अपने घरों पर खड़ी हो जाएगी। सकीना 10वीं पास है।

इस साल 747 सीजफायर उल्लंघन, LoC पर प्रभुत्व की रणनीति जारी रखेगी सेना

पिछले 15 सालों की तुलना में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से सबसे अधिक सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं 2018 में हुई हैं।

नई दिल्ली (एजेंसी)। सीमा नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर इस साल 747 बार सीजफायर उल्लंघन का सामना कर चुकी भारतीय सेना अपने प्रभुत्व की रणनीति जारी रखेगी। साथ ही कश्मीर में आतंकरोधी कार्रवाइयों के दौरान होने वाली क्षति को कम



करने की भी कोशिश करेगी। आर्मी कमांडरों के कांफ्रेंस में इन मुद्दों के साथ कट्टर युवाओं को मुख्धधारा में वापस लाने की जरूरत पर जोर दिया गया। साथ ही आतंकवाद विरोधी अभियानों को बाधित करने वाली पत्थरबाजी

की घटनाओं की भी समीक्षा की गयी।

शांति स्थापित करने की प्रक्रिया पर जोर

मोहम्मद अकरम डार ने गिरफ्तार युवकों की तत्काल रिहाई की मांग की। उन्होंने पुलिस को रात के दौरान छापों को बंद करने के लिए भी कहा। गिरफ्तारियों से पुलवामा शहर में वातावरण बिगड़ जाएगा। इसके गंभीर परिणाम निकलेंगे और साथ ही इन शिक्षित युवकों का कैरियर भी जोखिम में पड़ जाएगा।

शांति बिगाड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया हैं। साथ ही छापें जारी रहेंगे और आरोपी पत्थरबाजों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

अब तक 747 सीजफायर

778 किमी लंबे एलओसी पर इस साल मात्र 110 दिनों में 747 सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं हुई। यह आंकड़ा पिछले 15 साल की तुलना में

सबसे ज्यादा है। यह कहना गलत नहीं है कि सीजफायर उल्लंघन की घटनाओं में इजाफा हुआ है। सितंबर 2016 की 'सर्जिकल स्ट्राइक' के बाद सीमा पर शत्रुता में वृद्धि के साथ एलओसी पर 860 सीजफायर उल्लंघन हुआ और 2017 में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 120 घटनाएं हुईं। कांफ्रेंस में सेना के एक

सीनियर अधिकारी ने कहा, हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक पाकिस्तान भारत में आतंक का निर्यात रोकने के लिए ठोस कदम उठाता।

आंकड़ों के अनुसार, इस साल 40 से अधिक युवाओं ने जम्मू में आतंक का रास्ता चुना, जो पिछले साल 128 था। वहीं

इस साल अब तक 51 आतंकियों को मारा जा चुका है, जबकि इन ऑपरेशंस में 27 जवान भी शहीद हुए हैं।

एलओसी का लौ हुआ निक

कांन्फ्रेंस में चीन के साथ लड़ाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैले 'लाइन ऑफ एक्जुअल कंट्रोल' की 4057 किलोमीटर लंबी रेखा पर ऑपरेशनल स्थिति पर भी चर्चा हुई। ले. जनरल शर्मा ने कहा, 'सीनियर कमांडरों ने उत्तरी सीमाओं के साथ मौजूदा स्थिति की लंबाई पर विचार-विमर्श किया। साथ ही क्षमता निर्माण के प्रयासों, बुनियादी ढांचे के विकास और उपायों को आवश्यक प्रोत्साहन देने पर भी चर्चा की।

सख्त कानून बनाने की तैयारी में सरकार, मोदी-माल्या जैसे भगोड़ों की संपत्ति होगी जब्त

नई दिल्ली। बैंक से कर्जा लेकर विदेश भागने वाले अपराधियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 'भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश 2018' को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद आर्थिक अपराध कर देश छोड़कर भागने वाले ऐसे लोगों की संपत्ति जब्त की जा सकेगी। भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल को 12 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। लेकिन, कई मुद्दों पर गतिरोध के चलते बिल पास नहीं हो पाया था।

सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये प्रभावी हो जाएगा। इस अध्यादेश के प्रावधान ऐसे आर्थिक अपराधियों पर लागू होगा जिन्होंने विदेश से लौटने से इन्कार कर दिया है। जिनके खिलाफ निर्धारित अपराध को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। साथ ही ऐसे लोन डिफॉल्टर जिनके ऊपर 100 करोड़ से ज्यादा का लोन बकाया है। प्रावधान के तहत अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर बेच दिया जाएगा और उधारदाताओं को भुगतान किया जाएगा। ऐसे आर्थिक अपराधियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) के तहत मुकदमा चलेगा।

।sa महिला एजेंट ने आरोपित गौरव को फेसबुक पर किया ब्लॉक

आरोपित गौरव के कॉल डिटेल में दो संदिग्ध नंबर मिले हैं, दोनों नंबर पाकिस्तान के होने की आशंका है

रोहतक । पाकिस्तान को गोपनीय सूचनाएं भेजने के आरोप में गिरफ्तार सोनीपत (हरियाणा) के गज़ौर निवासी गौरव को अब आइएसआइ महिला एजेंट ने फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया है।

ताकि ट्रेस न हो सके लोकेशन

महिला ने शुक्रवार को उसे अनफ्रेंड व ब्लॉक किया है, ताकि पुलिस और खुफिया एजेंसियां उसकी लोकेशन ट्रेस न कर सकें। वहीं युवक की कॉल डिटेल में दो संदिग्ध नंबर मिले हैं, जो पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं।

इन नंबरों पर गौरव की आंखिरी बार बातचीत नवंबर में हुई थी। इसके बाद से वाट्सएप और फेसबुक पर बात हो रही थी। पुलिस फिलहाल इन नंबरों को भी ट्रेस कर रही है। वहीं गौरव के टट्टे हुए मोबाइल फोन से डाटा



रिकवर के लिए गुरुग्राम लैब में भेजा गया है। पुलिस का मानना है कि मोबाइल का डाटा रिकवर होने के बाद ही यह पता चल सकेगा कि गौरव और महिला एजेंट के बीच क्या-

1528306753 है। इस नंबर पर पिछले साल 12 नवंबर को शाम करीब पांच बजे बात हुई है। करीब डेढ़ मिनट तक बातचीत हुई है। इसी तरह



संपादकीय

महंगा होता तेल

वैसे मुहावरा तो तेल की धार देखने का है, लेकिन हमारे यहां अक्सर तेल की मार ही देखी जाती है। शुक्रवार को भारतीय बाजारों में पेट्रोल की कीमत पिछले 55 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। इस समय देश भर के पेट्रोल पंप पर आपको जिस कीमत पर पेट्रोल मिल रहा है, वह इसकी ऐतिहासिक बुलंदी से थोड़ा सा ही नीचे है। या यूं कहें कि यह इतिहास की दूसरी सबसे ऊंची बुलंदी है। लेकिन डीजल की कीमतों ने तो शुक्रवार को इतिहास ही बना दिया। इस समय जिस कीमत पर बाजार में डीजल मिल रहा है, उस कीमत पर वह इससे पहले कभी नहीं मिला। कीमत बढ़ने का सीधा दोष हम सरकार को नहीं दे सकते हैं। बहुत साल पहले जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, यह तभी तय हो गया था कि पेट्रोल की कीमतें अब अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ जाएंगी। जब वहां कच्चे तेल महंगा होगा, तो हमारे बाजार में पेट्रोल महंगा हो जाएगा और जब वहां यह सस्ता होगा, तो हमारे यहां सस्ता मिलने लगेगा। मौजूदा एनडीए सरकार भी उसी नीति को आगे बढ़ा रही है। इस सरकार ने बस इतना ही किया है कि उसने साप्ताहिक या मासिक निर्धारण की बजाय पेट्रोल की कीमत का अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से दैनिक निर्धारण शुरू कर दिया है। इसलिए अब हर रोज हमें पेट्रोल अलग दाम पर मिलता है। जहां तक अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात है, तो शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमत 75 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई है। यह पिछले चार साल का सबसे ऊंचा स्तर है। इस समय ओपेक देशों ने जिस तरह कच्चे तेल की आपूर्ति घटा दी है, उससे आने वाले दिनों में यह कीमत और ऊंची जाने की आशंका है। यानी हमारे बाजार में भी कीमतें बढ़ना लगभग तय है।आम जनता की नजर से देखें, तो आपति यही है कि जब दुनिया के बाजारों में कच्चे तेलों की कीमत बहुत कम थी, तो इसका लाभ भारतीय उपभोक्ताओं को बहुत ज्यादा नहीं मिला। शुरू में कुछ दाम भले ही घटे हों, लेकिन बाद में दुनिया के बाजार में इसकी कीमत भले ही जितनी भी नीचे आई हो, हमारे यहां इस पर कर भार बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल के दाम को जस का तस रहने दिया। यानी फायदा तो नहीं मिला, लेकिन अब जब दाम बढ़ रहे हैं, तो इसका घाटा जरूर भारतीय उपभोक्ताओं को डोलना पड़ रहा है। एक उम्मीद यह बनी थी कि अगर पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आ जाता, तो इस लमने वाले तरह-तरह के टैक्स खत्म हो जाएंगे और फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। लेकिन केंद्र और राज्यों की सरकारें अभी इसके लिए तैयार नहीं दिख रही।दुनिया के बाजार में कीमतें अगर इसी तरह बढ़ती रही, तो हमारी परेशानियों का बढ़ना लगभग तय है। पेट्रोल और डीजल के दाम जब बढ़ते हैं, तो सिर्फ आवागमन महंगा ही होता, इससे किराया भाड़ा भी बढ़ता है और तकरीबन हर चीज के दाम ऊपर की ओर जाने लगते हैं। किसानों के लिए सिंचाई भी महंगी हो जाती है और बहुत सी चीजों की लागत भी बढ़ जाती है। उर्वरक समेत वे सारी चीजें महंगी होने लगती हैं, जिनके उत्पादन में पेट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल महंगा होने के तौर पर होता है। पेट्रोलियम पदार्थों की वजह से बढ़ने वाली मुद्रास्फीति ने देश को कई बार परेशान किया है। यह फिर न हो इसके लिए केंद्र और सरकारों को पेट्रोलियम पदार्थों पर लागू कर संरचना को बदलना होगा। जीएसटी के जमाने में पेट्रोल पुराने तरीके से नहीं चलना चाहिए।

अस्पतालों पर नजर

अस्पतालों में मरीजों के इलाज की कोई मॉनिटरिंग पणाली यदि विकसित हो तो उसका निस्संदेह स्वागत किया जाएगा। अभी तक अस्पताल में मरीज भर्ती होते हैं और उनका जो भी इलाज डॉक्टर करते हैं, वह अस्पताल तक ही सीमित रहता है। उस पर कहीं एक केंद्रीय पणाली से नजर रखी जाए तथा वहां से ही अस्पतालों को आवश्यकता पड़ने पर मार्ग निर्देश मिले। इसका सुझाव विशेषज्ञ लंबे समय से दे रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस संदर्भ में जल्द ही आउटपुट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम (पोर्टल) बनाने की घोषणा की है, उसे पहली नजर में उचित कहा जाएगा। इसके लिए मंत्रालय एनएबीएच के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाने की दिशा में काम कर रहा है जिससे विभिन्न अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की गुणवत्ता पर रियल टाइम नजर रहेगी। इससे देश के सभी अस्पतालों को जोड़े जाने की योजना है। इस पोर्टल के जरिए सभी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों, उनका इलाज, ऑपरेशन, उसे किस डॉक्टर ने अंजाम दिया, मरीज के आईसीयू व वेंटीलेटर पर रहने की अवधि के साथ इलाज के दौरान मरने वालों तक की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। ऐसा हो जाए इसमें दूरस्थ मरीजों के बारे में वहां के डॉक्टर विशेषज्ञों से सुझाव लेकर उनका बेहतर इलाज कर सकते हैं। इसके और भी कई लाभ हो सकते हैं। मसलन, अस्पताल की कमियों की ओर ध्यान जाएगा जिसे दूर किया जा सकता है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या वाकई इतना बड़ा तंत्र विकसित हो पाएगा जहां से वाकई इतनी पैनी नजर रखी जा सके? यह काम आसान नहीं है। देश के सभी अस्पतालों को जोड़कर लाखों की संख्या में मरीजों के इलाज एवं उनकी स्थिति पर नजर रखने की स्थिति यों ही निर्मित नहीं हो सकती। भारत में अभी इंटरनेट की स्थिति को देखते हुए शायद सारे अस्पतालों को जोड़ना संभव नहीं हो। हालांकि कहा जा सकता है कि जितना भी होगा वह मरीजों के हक में ही होगा। हम न भूलें कि सरकार पहले से ही मेरा अस्पताल नाम का एप, पोर्टल और एसएमएस पणाली विकसित कर चुकी है। कहा जाता है कि अस्पताल से छुट्टी होने के साथ ही मरीजों से उनकी संतुष्टि आदि के संबंध में प्रश्न किए जाते हैं। पता नहीं कितने मरीजों से पूछा जाता है, कितने जवाब देते हैं। फिर उन जवाबों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं यह भी हमें नहीं पता। सच तो यह कि इस पणाली की जानकारी भी अभी तक सभी को नहीं है। इसका भी योजनानुसार क्रियान्वयन करने के लिए अभी काफी काम करने की जरूरत है।

कटाक्ष/ कबीरदास

भाईबंदी की बात

भाई हम तो सुनीत कुमार सिंह के साथ हैं। बेचारे के साथ ज्यादाती पर ज्यादाती हो रही है। पुलिस के इस्पेक्टर भी बने तो यूपी में। उस पर एकदम सूखी पॉलिटिंग मिली, झांसी में। उसके भी ऊपर से एकआउंटर राज आ गया। सरकारी वदी बवाने के लिए बंदे मारकर लाओ। वनां सस्पेंड। नयी टैक्नॉलॉजी सिंह साहब की दुश्मन हो गयी। बंदे को सिर्फ एक फोन कॉल के लिए सस्पेंड कर दिया गया! बेशक, लेखराज यादव ने सुनीत कुमार सिंह के साथ दगा की है। उसने सिंह साहब की निजी बातचीत, सारी दुनिया को सुना जो दी है। पर कई-कई मामलों के अपराधी यादव से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? पर सुनीत सिंह को यों शराफत की सजा दिया जाना क्या सही है? उन्होंने तो भाईबंदी में यादव को फांसीवाड़न दी थी। वह भी छोटी-मोटी नहीं, एन्काउंटर से बचाव वाली एडवाइज। सताइसवार पार्टी के विधायक और जिला अध्यक्ष से कुछ ले-देकर निपटारा करा लेने की एडवाइज। बेचारे सिंह साहब इस कलियुग में रखवाले साइयां बनकर दिखा रहे थे। पर सरकार ने हाथ के हाथ सस्पेंड ही कर दिया। और वह भी किसलिए? सिंह साहब ने गैंगस्टर को पहले से वेता क्यों दिया कि उसके एन्काउंटर की तैयारियां हो रही हैं? जान बवानी है तो राज करने वालों को खुश कर के दिखाए। लेकिन, इसमें आपत्ति ठीक-ठीक किस चीज पर की जा रही है? एन्काउंटर की चेतावनी देने पर या राज करने वालों की शरण लेने का संदेश देने पर? पर क्या किसी की जान बवाना गुनाह है और वह भी तब जबकि उसी में सब का फायदा हो। गैंगस्टर जा की भाी, राज करने वालों का भी। और खुद पुलिस का भी। एक-एक कर सारे अपराधी यों ही सुधरने का सरकारी टप्पा लगाव आए, तो पुलिस का काम कितना आसान हो जाएगा? वैसे भी अपराधी को खत्म करने का जो काम पुलिस की गोली करती है और वह भी तरह-तरह के विवाद पैदा करते हुए, वही काम तो अपराधियों के गले में डाला जाने वाला अपराध-मुक्ति का सरकारी पट्टा करता है, बिना किसी विवाद के। अब इतनी ट्रिगर हैप्पी तो योगी सरकार भी नहीं है कि जहां बोली से काम निकलता हो, वहां भी गोली चलाने का तकजा करेगी?

क्या रुस और अमेरिका मिलकर साल पुराने इस बर्बर गृह युद्ध का कोई टिकाऊ राजनीतिक समाधान निकालेंगे?

उम्मा उपलब्धियां

समृद्ध खेल दर्शन चाहिए देश को

खेती-किसानी

आसमान से बरसी आफत

फ़ेड वीर

पिछले सप्ताह के अंत में सीरिया के कथित रासायनिक हथियारों के टिकानों पर अमेरिका के नेतृत्व में मिसाइल हमले किए गए। इन हमलों के बाद रुस ने कहा कि इनसे वास्तव में कुछ भी नहीं बदला है।
ऋेमलिन के करीबी विश्लेषकों का कहना है कि मारको बशर अल-असद के सैन्य अभियानों को अपना समर्थन देता रहेगा, और इसके साथ ही वह शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रयास भी जारी रखेगा। अमेरिका व इसके साथी देशों को किनारे करते हुए रुस ने पिछले साल ईरान व तुर्की के साथ मिलकर एक शांति प्रक्रिया की शुरुआत की थी।
रूसी विश्लेषकों की राय में रुस का नेतृत्व इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्चस्त है कि अमेरिका के पास सीरिया की समस्या का कोई सुसंगत समाधान नहीं है और उसके नए मिसाइल हमलों व युद्धग्रस्त सीरिया के एक तिहाई हिस्सों पर स्थानीय सहयोगियों के साथ मिलकर लगातार कब्जा जमाए रखने का मकसद सिर्फ विघ्न डालना है। पिछले सप्ताह युद्ध जैसी घोषणाओं में रुस ने इस बात के साफ संकेत दिए थे कि यदि अमेरिकी मिसाइलों से एक भी रूसी नागरिक को नुकसान पहुंचा, तो भूमध्यसागर में अमेरिकी जंगी पोतों पर जवाबी कार्रवाई करने से वह कतई पीछे नहीं हटेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रुस पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि ‘तैयार रहें’।
सुयोग है कि यह नाटकीय मुद्रा तक सीमित रहा। यह साफ है कि सीरिया में रुस और अमेरिका की सैन्य टीमें कुछ यूं आपसी समन्वय के साथ सक्रिय हैं कि भूलकर भी उनकी आपसी भिड़ंत न हो, इसका अंदाज इस बात से भी हुआ कि 13 अप्रैल की रात जब अमेरिकी मिसाइलें सीरियाई टिकानों पर आग उगल रही थी, रूसी हवाई सुरक्षा निष्क्रिय कर दी गई थी और कोई भी क्रूज मिसाइल सीरिया में रूसी टिकानों के इर्दगिर्द भी नहीं फटकी।

इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए-कनाडा स्टडीज के उप-निदेशक पॉवेल जोलोतारेव के मुताबिक, ‘रूस की आधिकारिक प्रतिक्रिया मिसाइल हमलों को गलत और गैरकानूनी करार देती है और औपचारिक निंदा करती है। अपनी टिप्पणी में रुस ने यह आरोप लगाया है कि ‘ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोडिक्शन ऑफ कॅेमिकल वीपन्स’ के जांचकर्ताओं की टीम डूमा में कथित रासायनिक हथियारों के टिकानों की पड़ताल शुरू करने ही वाली थी कि उसके ऐन पहले ये हमले कर दिए गए। साफ है, अमेरिकी नेतृत्व इन इस्पेक्टरों की जांच तक भी सब्र रखने को तैयार न था। यह बताता है कि वे सैन्य कार्रवाई करना चाहते थे।’
जोलोतारेव ने आगे कहा कि ‘यह संयोग है कि पेंटागन और रूसी रक्षा मंत्रालय एक-दूसरे के करीबी संपर्क में हैं। और उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया कि वहां समस्याएं नहीं पैदा होने दी जाएंगी। इसलिए मिसाइल हमलों की प्रकृति राजनीतिक और प्रतीकात्मक अधिक थी। फिर भी, इन्होंने पहले से ही खराब

उम्मा उपलब्धियां

समृद्ध खेल दर्शन चाहिए देश को

उस समय विरले ही इनका हाथ थामने को आगे आते हैं। महिलाओं, दलितों व अल्पसंख्यक सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले खिलाड़ियों के संदर्भ में यह हकीकत और भी भयावह रूप में सामने आती है। कई प्रतिभाएं उपयुक्त खेल सुविधाओं, सही कोचिंग, किट व डाइट के अभाव में रास्ते में ही दम तोड़ जाती हैं। चयन में व्याप्त भाई-भतीजावाद द्वारा कितनों के ही पंख कतर दिए जाते हैं। कितनी ही यौन शोषण की शिकार प्रतिभाएं सालों साल अपना दर्द साथ लिए

रास्ते तलाशने को मजबूर होती हैं। यह हमारे लिए विचारणीय सवाल होना चाहिए। फिलहाल तो उनकी मुख्य भूमिका यही नजर आती है कि जब ये खिलाड़ी अपने परिवारों के तमाम बजट को निचोड़ कर, ऐंडी चोटी का जोर लगाकर मैडल जीत लेते हैं तो राजनेताओं व समाज के नेताओं में इनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़-सी लगती जाती है। जिस समय ये खिलाड़ी आर्थिक-सामाजिक तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों से जुड़ा रहे होते हैं,

क्षमता से रिश्ता अभी कायम ही नहीं हुआ। वरना ये कैसे हो जाता कि पंजाब जैसे राज्य का बड़ा नौजवान तबका नशे की चपेट में चला जाए और हम कुछ कर ही न पाएं। खेलों में नौजवान तबके को

सुजानात्मकता के साथ जोड़ने को ताक़त है। बशर्तें की हम उसे पहचानें और उस जगह से खेलों से रिश्ता कायम करें। उस प्रक्रिया से मैडलों की खेती लहलहाएगी। इस नज़रिए में यह जरूरी है कि गांवों व शहरों में खेलों का सुदृढ़ ढांचा खड़ा करना हमारी पहली प्राथमिकता हो। सही क़दम से चीज़ें काफी हद तक सही दिशा में बदलना शुरू हो जाएंगी। किसे नहीं पता

कि मैडल जीतने के बाद करोड़पति बनाना उस प्रतिभा को भुनाने वाला रिश्ता है और इसी वजह से खेलों में मालामाल होने की ललक खिलाड़ियों को ड़ग सेवन की तरफ भी धकेलती है। पूरे खेल का कमर्शियलाइजेशन खेल भावना को मारता है। खेल सुविधाओं के अभाव में उभरती हुई खेल प्रतिभाएं निजी खेल अकादमियों के शोषण का शिकार होती जा रही हैं। जिस दिन पूरा देश राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के तीसरे स्थान की खुशी मना रहा था, साथ में यह खबर भी चल रही थी कि

खेती-किसानी

आसमान से बरसी आफत

फसल को सही तरीके से आंका नहीं जाता। मुआवजा उन्हें मिलता है, जो पटवारी या सरपंच के नजदीकी होते हैं। ऐसी स्थिति में जरूरतमंद किसान हाथ मलता रह जाता है। गौर करने वाली बात यह है

कि भारत में बारिश दो मॉनसूनी सत्रों में होती है। एक मुख्य, जो बरसात का मौसम होता है। दूसरा सर्दियों के आखिर में भूमध्यसागरीय चक्रवात के सक्रिय होने पर। लेकिन यह लगातार दूसरा साल रहा है जब बेमौसम बरसात हुई। यही वजह रही कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड सहित कई अन्य राज्यों में खेती-किसानी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। साफ है, परेशानियां हर तरफ होंगी। हालांकि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल को ध्यान इस तरफ नहीं गया है। जाहिर है, हमारे यहां राजनीतिक पार्टियों

को अपने इन ‘‘अन्नदाताओं’ की याद तभी आती है जब चुनाव सिर पर आते हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा वोट बैंक भी यहीं है। लेकिन सत्ता की चाभी हाथों तक पहुंचते ही देश की सबसे बड़ी साधनहीन

आबादी को उसकी तकदीर पर छोड़ दिया जाता है।इससे पहले आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया कि औसतन एक किसान की सालाना आमदनी 20 से 30 हजार रु पये है। तो क्या ये माने कि पांच साल बाद इस किसान की सालाना

आमदनी 40 हजार से 60 हजार रु पये हो जाएगी। अगर हो भी गई तो क्या इस बात का दावा किया जा सकता है कि महंगाई का आंकड़ा दोगुना या उससे अधिक नहीं होगा। दूसरी अहम बात यह कि खेती-किसानी पर लगातार आपदा की वजह से किसान

विदेश नीति संबंधी एक जर्नल रसिया इन ग्लोबल अफेयर्स के संपादक फियोडोर लकियानोव का कहना है कि ‘ सीरिया के सैन्य हालात एक साल पहले के मुकाबले आज बेहतर हैं। मगर तुर्की और ईरान के साथ कई बैठकों के बावजूद कोई राजनीतिक समाधान आसपास नहीं दिख रहा। रुस का इन दोनों साथी देशों के साथ रिश्ता बेहद जटिल है। पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ अफने रिश्ते को पटरी पर लाने के लिए खूब मशक्कत कर रहे हैं, मगर उनका कोई प्रयास कारगर नहीं साबित हो रहा।’
तुर्की ने अमेरिकी मिसाइल हमलों की हिमायत में जहां बयान जारी किए हैं, वहीं ईरान मारको से इस बात से खफा है कि वह इन हमलों को रोकने में नाकाम रहा। पश्चिम एशिया के विश्लेषक व्लादिमीर सोलिनकोव का कहना है कि ‘अब यह स्पष्ट हो रहा है कि अमेरिका और रुस के बीच सहयोग के बिना सीरिया की समस्या का कोई भी कारगर समाधान नहीं निकल सकता।’
इसका सीधा सा मतलब है कि रुकी हुई जेनेवा शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ेगा। इस शांति प्रक्रिया में अमेरिका और उसके साथी देशों की सक्रिय भागीदारी थी। सोलिनकोव आगे कहते हैं कि अमेरिकी के हालिया मिसाइल हमलों के बाद स्थितियां अधिक जटिल हो गई हैं। रुस को चिंता है कि अमेरिकी कभी भी इसे दोहरा सकते हैं। लेकिन सीरिया में दोनों देशों के बीच संवाद अब भी कायम है, बल्कि वह संवाद काफी प्रभावकारी है, और इसीलिए उम्मीद बंधती है कि सीरिया की मौजूदा दर्दनाक तस्वीर बदलेगी।

खेती-किसानी

देश की उभरती आकांक्षा ‘मिलेनियम सिटी’ गुडगांव से 8वें मील पर (धामडोज) में फूटबॉल टीम व उनके कोच वन मन्त्री व उनके लोगों को उनके खेल मैदान पर बदनीयत के खिलाफ़ आमरण अनशन पर।

दूसरी तरफ़ खेल संगठनों की कार्यप्रणाली व चरित्र को भी जान खेल संस्कृति के अनुरूप ढालने की सख़्त ज़रूरत है। राजनेताओं व अफसरशाही से इन्हें मुक्त करके इनमें असल खेल प्रेमियों व इस क्षेत्र की प्रतिभाओं से लैस करना चाहिए। इसके लिए सरकार को खेल बजट में पर्याप्त वृद्धि करते हुए खेल संघों की इन लोगों पर निर्भरता ख़त्म करनी होगी। उभरते हुए तबकों जैसे महिलाएं, को ज्यादा से ज्यादा खेल जगत को स्वरूप देने में शामिल करना होगा।

अभी तक खेल संघों व नीति निर्धारण में उनकी समावटी मात्र भागीदारी ही है। ओलम्पिक खेलों के एकदम बाद प्रधानमंत्री द्वारा गठित आठ सदस्यीय खेल टास्क फ़ोर्स में भी एक भी महिला नहीं रखी गई है जबकि ओलम्पिक में मैडल तो वही जीत कर लाई थी। उससे दह ग्पाद होकर स्वयं प्रधानमंत्री ने ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को बेटी खिलाओ’ तक विकसित करने का आह्वान किया था। आज अपनी हिम्मत और हौसले के आधार पर अपना स्थान बनानी प्रतिभाओं के विचारों, अनुभवों और आकांक्षाओं को शामिल करने से ही खेल दर्शन समृद्ध होगा। दुनिया की खेल ताक़तों द्वारा उनके यहां विकसित हो रही खेल संस्कृतियों का रास्ता इन्हीं मुकामों से होकर गुज़रा है।

खेती-किसानी

भीषण कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक घाटे का सोदा होने की वजह से हर रोज़ ढाई हजार किसान खेती छोड़ रहे हैं और हर दिन 50 के करीब किसान मौत को गले लगा रहे हैं। और तो और, देश में अभी किसानों की कोई एक परिभाषा भी नहीं है। वित्तीय योजनाओं में, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो और पुलिस की नजर में किसान की अलग-अलग परिभाषाएं हैं। जाहिर है, घटती आमदनी के चलते किसान निराश हैं हालांकि मोदी सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए इस बार संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। लेकिन सरकार इस लक्ष्य को कैसे पूरा करेगी, यह अपने आप में एक गंभीर सवाल है। क्योंकि हमारे यहां खेती- किसानी के जो वर्तमान स्थिति है, वह काफी दयनीय है। ऐसे में अगर किसानों की आय दोगुनी करनी है तो कृषि की वृद्धि दर हर साल 14 प्रतिशत तक ले जानी होगी। उसके लिए एक तरफ़ खेती की उत्पादकता बढ़ानी होगी और दूसरी तरफ़ न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने होंगे। इन दोनों मोर्चों पर कोई बड़ी अब तक दिखाई नहीं दिया है। बहरहाल, नया युवक इस खेती के धंधे में आना नहीं चाहता। सारे ग्रामीण शहरों की चकावंधे देख शहरों की ओर भाग रहे हैं और जो बचे हैं, वे विदग्ध जैसे प्रांत में आत्महत्या कर रहे हैं। ग्रामीण भारत में सबको अन्न देने वाला किसान आज भूखा मर रहा है।

सार-समाचार

रूस का दावा, सीरिया में अटक कर अमरीका ने नहीं की रेड लाइन क्रॉस



मास्को। रूस ने कहा है कि अमरीका ने सीरिया पर अटक कर रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमरीका ने उनसे फोन पर बात कर कहा कि उन्होंने कहा कि सीरिया में हमारी रेड लाइन कहां थी, तब अमरीका ने बताया कि उन्होंने अटक कर किसी भी रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया है। सीरिया पर 7 अप्रैल को हुए केमिकल अटक के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराते हुए अमेरिका ने सीरियाई मिलिट्री बेस पर हवाई हमले कर जवाब दिया था।

रूसी विदेश मंत्री के अनुसार, अमरीका ने उन्हें कहा कि सीरिया में रूस की उपस्थिति को सम्मान करते हैं और उन्होंने वहां किसी भी प्रकार के रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया है। अगर रूस के दावे को स्वीकार किया जाए, तो सीरिया अटक के बाद अमरीका की तरफ से यह पहला सकारात्मक बयान है। विदेश मंत्री लावरोव ने साथ में यह भी कहा कि पिछले माह पुतिन की जीत के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई देते हुए व्हाइट हाउस आने के लिए निमंत्रण दिया था।

लावरोव ने कहा कि अगर पुतिन व्हाइट हाउस की यात्रा करते हैं, तो रूस और अमरीका के बीच यह एक पारस्परिक दौरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि रूस के अधिकारी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहते हैं, लेकिन अपमानित भी नहीं होना चाहते हैं। लावरोव ने कहा कि पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति से मीटिंग के तैयार है। रूस और अमेरिका के रिश्तों शीत युद्ध के बाद सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। 2014 में यूक्रेन विवाद, सीरिया युद्ध, 2016 यूएस इलेक्शन में मास्को की दखलंदाजी और ब्रिटेन में रूसी जासूस पर केमिकल अटक जैसे ताजा विवादों ने दोनों ही देशों को हथियारों की लड़ाई को मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है।

मुस्लिम धर्मगुरु का फेसबुक को लेकर फतवा जारी



रोम। मिस्त्र में रहने वाले एक मुस्लिम धर्मगुरु शकवी अल्लाम ने फेसबुक लाईक को लेकर अनोखा फरमान जारी करते कहा कि "सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लोगों से फर्जी लाइक करवाना सरासर गलत है। लाइक्स की खरीद-फरोख्त करना इस्लाम के अंतर्गत हराम माना जाता है।"

धर्मगुरु शकवी अल्लाम ने इस संबंध में एक फतवा भी जारी किया है, जिसमें सोशल मीडिया से जुड़ी कई चीजें शामिल हैं। शकवी अल्लाम मिस्त्र में ग्रैंड मुफ्ती हैं। वह यहां पर लोगों को इस्लाम से जुड़े कानून और वैधानिक मामलों के बारे में बताते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु ने इस बाबत अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने इसमें कहा, "अगर लाइक्स नकली हों, तब इस चीज को नाजायज समझा जाना चाहिए, जो एक किस्म की जालसाजी या धोखाधड़ी भी है।"

आगे एक हदीस (पैगंबर मोहम्मद के कथन) का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "जो धोखा देता है, वह हममें से नहीं है।" हालांकि, धर्मगुरु ने इसी के साथ यह भी स्पष्ट किया कि दर्शकों (ऑडियंस) को बढ़ाने के लिए विज्ञापन चलाना, जिससे कि लाइक्स में भी बढ़ोत्तरी होती है, यह चीज हराम नहीं है, क्योंकि वे लाइक्स असली होते हैं।

अमेरिका:पूर्व छात्र ने स्कूल में की अंधाधुंध गोलीबारी, 1 घायल, आरोपी गिरफ्तार

फ्लोरिडा में एक बार फिर स्कूल में गोलीबारी हुई। हदसे में एक छात्र घायल हो गया है।

फ्लोरिडा (एपी)। फ्लोरिडा में एक बार फिर स्कूल में गोलीबारी की घटना सामने आई। हादसे में एक छात्र घायल हो गया है। खबरों के अनुसार संदिग्ध गिटार केस में शॉटगन छुपा कर लाया था।

मौका पाते ही हमलावर ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। अध्यापक और छात्र अपनी जान बचाने के लिए बेंच और दरवाजों के पीछे छुप गए। हमलावार एक 19 वर्षीय युवक था। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक को जब हथकड़ी पहनाई गई, वह डर गया और माफी मांगने लगा। इस हादसे में स्कूल के 17 वर्षीय बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। उसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। संदिग्ध की पहचान स्काई बाउच के रूप में की गई है। पकड़े जाने के बाद युवक ने वहां मौजूद संवाददाता से कहा कि



मुझे माफ कर दो। उसने आगे कहा कि मैंने किसी पर गोली नहीं चलाई। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वाउज स्कूल का ही पूर्व छात्र है।

बता दें कि दो महीने पहले भी फ्लोरिडा के स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल में फायरिंग में 17 लोगों की मौत हो गई थी। स्कूल के पूर्व छात्र निकोलस कर्जु ने स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल में वेलेंटाईंस डे के दिन एआर-15 ऑटोमैटिक राइफल से 15 छात्रों और दो स्टाफ मेंबर्स की हत्या कर दी थी।

अमेरिकी स्कूल में गोलीबारी की दूसरी सबसे बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला कर्जु इसी स्कूल में पढ़ता था। उसे अनुशासनहीनता के आरोप में पिछले साल स्कूल से निकाल दिया गया था।

भारतीय पुलिस और सुरक्षाबल करते हैं शक्तियों का दुरुपयोग-अमेरिकी विदेश विभाग



अमेरिकी विदेश विभाग ने मानवाधिकार रिपोर्ट में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा उल्लंघन के लिए भारत की आलोचना की है।

न्यूयॉर्क। अमेरिकी विदेश विभाग ने मानवाधिकार रिपोर्ट में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा किए गए अपराध के लिए भारत की आलोचना की है। सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों में पुलिस और सुरक्षा बल के दुरुपयोग शामिल थे। जिनमें असाधारण हत्याएं, गायब होना, यातना, मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत, दुष्कर्म, कठोर और खतरनाक जेल की धमकी और लंबी प्रत्याशित हिरासत जैसे आरोप शामिल हैं।

अमेरिका ने शुक्रवार को 2017 की मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर राज्य, पूर्वोत्तर और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में अलगाववादी विद्रोहियों और आतंकवादियों ने सशस्त्र बलों के कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों और नागरिकों की हत्याओं और यातना सहित गंभीर दुर्व्यवहार किया और इसके लिए बाल सैनिकों का उपयोग किया गया।

इस रिपोर्ट का प्रकाशन ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके प्रशासन पर अमेरिकी अधिकारियों ने नागरिक अधिकारों के हनन और मीडिया पर हमला करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत में मीडिया आउटलेट की सेंसरशिप और उत्पीड़न जिसमें सरकार की कुछ आलोचनाएं जारी रहें। इस रिपोर्ट की कई अन्य देशों की भी आलोचना की गई है।

'Google' का यह एंड्रॉयड ऐप साइबर अपराधियों के लिए एक 'गिफ्ट' जैसा है

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने

गूगल की चैट सुविधा पर

सवाल उठाए हैं। उसका कहना

है कि यह साइबर अपराधियों

और सरकारी जासूसी के लिए

एक गिफ्ट की तहत होगा।



सैन फ्रांसिस्को। गूगल ने व्हाट्सऐप और अन्य मोबाइल मैसेजिंग ऐप की तहत खुद का चैट ऐप लॉन्च करने का फैसला किया है। सच इंजन कंपनी एक नई चैट ऐप पर काम कर रही है और संभव है कि जल्द यह लॉन्च भी हो जाएगी। कंपनी ने इसका नाम Chat रखा है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गूगल की चैट सुविधा पर सवाल उठाए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि गूगल का यह निर्णय एंड्राइड यूजर्स की गोपनीयता की पूरी तरह से अवमानना दिखाता है। यह

साइबर अपराधियों और सरकारी जासूसी के लिए एक गिफ्ट की तहत होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई चैट सेवा में मैसेज इंटरनेट के जरिए नहीं बल्कि मोबाइल फोन से भेजे जा सकेंगे, यानि एसएमएस के जरिए। इस हफ्ते 'द वर्ज' के एक बयान में, गूगल प्रवक्ता ने पुष्टि की कि नई सेवा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग नहीं करेगी और गूगल अपने मौजूदा मोबाइल मैसेजिंग ऐप 'एलो' में निवेश रोक रहा है, जिसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को तकनीकी कंपनियों के लिए न्यूनतम आवश्यकता मानता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मैसेजिंग ऐप्स में निजी जानकारी निजी रहती है।

क्या है एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

चीन बोर्डिंग और एयरबस का सबसे बड़ा सप्लायर, 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इन देशों के बेचे हैं

बीजिंग (प्रेट्र)। चीन के विमान निर्माता कंपनियों ने कहा है कि 50 से अधिक चीनी निर्मित विमान जिनका उपयोग यात्री और कार्गो परिवहन दोनों के लिए किया जा सकता है, उन्हें आठ बेल्ट और रोड देशों में पहुंचा दिया गया है। एवीआईसी हॉर्बिन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप (एचएआईजी) कंपनी लिमिटेड ने कहा कि नवीनतम दो Y-12E विमानों को 17 अप्रैल को नेपाल को वितरित किए गए थे, जहां उनका उपयोग कुछ दूरियों के घरेलू परिवहन के लिए किया जाएगा।

नेपाल ने इसके पहले पहले क्रमशः 2014 और 2017 में दो Y-12E खरीदे

थे। दोनों विमानों ने अब तक 1,725 से अधिक सुरक्षित उड़ान रिकॉर्ड किए हैं। राज्य की शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि विमान 2015 में भूकंप से पीड़ित लोगों के मदद के लिए परिवहन में पहुंचा दिया गया है। पूर्वोत्तर चीन के हॉर्बिन में स्थित हेग अंतरराष्ट्रीय विमानन उद्यमों जैसे बोइंग और एयरबस का एक बड़ा सप्लायर है। इसने अब तक स्वतंत्र रूप से कई प्रकार के हेलीकॉप्टर और हल्के क्षेत्रीय विमान विकसित किए हैं।

बड़े पंखों वाले दो इंजन के Y-12 श्रृंखला के विमान हल्के और सामान्य उद्देश्य के लिए होते हैं जिसे यात्री और कार्गो

परिवहन के साथ-साथ पैराशूट और जॉपिंग के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। हेग ने संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस समेत दुनिया भर के 30 से अधिक देशों और क्षेत्रों में झू-12 श्रृंखला के विमान बेचे हैं। अरबों डॉलर के वन बेल्ट वन रोड (ओबोर) जिसमें विवादस्पद चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में बंदरगाहों, राजमार्गों और रेलवे सहित कनेक्टिविटी परियोजनाओं का निर्माण करना है। आपको बता दें कि भारत ने सीपीईसी का शुरु से ही विरोध किया था क्योंकि इसका निर्माण पाकिस्तान-कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होते हुए किया जा रहा है।



चीन ने भी उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने के फैसले का किया स्वागत

बीजिंग। चीन ने आज कहा कि वह उत्तर कोरिया के परमाणु और इंटरकांटिनेंटल मिसाइल परीक्षण पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत करता है। थ्योंगयांग के मुख्य सहयोगी चीन ने कहा कि यह कदम पड़ोसी इलाकों में डीन्यूक्लराइजेशन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने अपने एक बयान में कहा, "चीन का मानना है कि परमाणु परीक्षण रोकने, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने का उत्तर कोरिया का निर्णय सराहनीय है।

इस फैसले से कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति बेहतर होगी और साथ ही डीन्यूक्लराइजेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।" चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि "चीन उत्तरी कोरिया का अन्य संबंधित पार्टियों (दक्षिण कोरिया और अमेरिका) के साथ द्विपक्षीय वार्ता को समर्थन



करता है।" उत्तरी कोरियाई नेता किम जोंग उन ने डेमिलिटराइज्ड जोन में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में दक्षिण कोरियाई नेता मून जे इन से मुलाकात कर ली है। आपको बता दें कि कोरियाई प्रायद्वीपों के नेताओं की ये मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ किम की आगामी बहुप्रतीक्षित मुलाकात के पहले हुई है। गौरतलब है कि डेमिलिटराइज्ड जोन वह जगह है जो दोनों प्रायद्वीपों (उत्तर-दक्षिण कोरिया) को आपस में अलग करती है। हालांकि, किम ने इस तरफ कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन थ्योंगयांग अपने परमाणु हथियारों के परीक्षण को छोड़ने के लिए तैयार है। बताया जाता है कि उनके अधिकतर मिसाइल परीक्षण अमेरिकी क्षेत्र तक किये जाते थे, जिसके बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव बढ़ गए थे। गौरतलब है कि, सालों से उत्तर कोरिया में अर्थव्यवस्था और विकास की गति काफी पीछे है।

पाक कोर्ट का गृह मंत्रालय को आदेश- किरण बाला मामले पर तीन दिन में ले फैसला

लाहौर (एजेंसी)। पाकिस्तान की लाहौर कोर्ट ने किरण बाला उर्फ आमना बीबी की अर्जी पर तीन दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह पाकिस्तानी नागरिकता और अपने वीजा की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने वाली किरण बाला की अर्जी पर तीन दिन के अंदर निर्णय करे।

पंजाब में होशियारपुर के गांव गढ़शंकर की रहने वाली हिंदू परिवार की किरण बाला 12 अप्रैल को सिख श्रद्धालुओं के जत्थे में शामिल होकर अटारी से विशेष रेल गाड़ी से श्री पंजा साहब गई थी। वहां उसने अपने फेसबुक दोस्त मोहम्मद आजम के साथ लाहौर की जामा मस्जिद में इस्लाम कुबूल किया। वहीं पर निकाह के बाद उसने अपना नाम आमना बीबी रख लिया था।

लडुकी के परिजनों को इस बात का पता उस समय चला जब युवती ने इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान विदेश विभाग के कार्यालय में एक अर्जी दायर की। इसमें युवती ने कहा है कि उसने अपनी मर्जी से लाहौर निवासी



मोहम्मद आजम से निकाह किया और वह 21 अप्रैल को भारत लौटने वाले जत्थे के साथ वापस नहीं जाएगी। इसमें यह भी लिखा है कि उसके वीजा की अवधि 21 अप्रैल को खत्म हो रही है, इसलिए उसे अगले तीन महीने का वीजा दिया जाए, ताकि वह पाकिस्तान में रह सके। किरण बाला के वकील इजाज अहमद खान ने अदालत से कहा कि वह पाकिस्तान के राष्ट्रीयता और

उनके वीजा में विस्तार के लिए विदेश मंत्रालय में दो आवेदन कर चुके हैं। किरण का वीजा 21 अप्रैल को समाप्त होने वाल है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता पाकिस्तानी नागरिकता हासिल करने के लिए सत्यापन के लिए तैयार है।

ससुराल में पाकिस्तान पुलिस का पहरा

फिलहाल किरण बाला उर्फ आमना बीबी इस समय मुल्तान रोड लाहौर में अपने ससुराल घर में हैं। उसके ससुराल के घर को पाकिस्तान पुलिस की ओर से चारों ओर से घेर रखा गया है ताकि वीजा न मिलने की सूरत में उसे सिख जत्थे के साथ ही भारत भेजा जा सके।

केंद्र सरकार दे दखल, किरण की न बढ़े वीजा अवधि-तरसेम

पाकिस्तान में निकाह करने वाली किरण बाला के ससुरा तरसेम सिंह ने गुहार लगाई है कि उनकी बहू की वीजा अवधि न बढ़े। इसके लिए केंद्र सरकार दखल दे। उन्होंने गढ़शंकर के पूर्व विधायक लव कुमार गोल्डी से इस मसले के मुख्यमंत्री केप्टन अमरिंदर सिंह के ध्यान में लाने की फरियाद की है।

